भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-132
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

शुल्क भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग

†132. **श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर के स्कूलों में शुल्क भुगतान के लिए यूपीआई और अन्य डिजिटल लेनदेन पद्धतियों के उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;
(ख) यदि हाँ, तो देश में शुल्क भुगतान के साधन के रूप में यूपीआई स्वीकार करने वाले सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में यूपीआई के माध्यम से सरकारी स्कूलों द्वारा प्राप्त शुल्क और अतिरिक्त भुगतान की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-बार कुल राशि कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने स्कूली शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए यूपीआई का उचित उपयोग करने और अभिभावकों/स्कूली बच्चों को इस संबंध में सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने शुल्क भुगतान के लिए स्कूलों में यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रचार कार्यकलाप/अभियान चलाया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): भारत सरकार जीवनयापन और स्कूल शिक्षा को सुगम बनाने के लिए स्कूलों में यूपीआई सहित वित्तीय लेनदेन के डिजिटल तरीकों के उपयोग का पुरजोर सहयोग कर रही है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और स्कूलों में डिजिटल भुगतान तंत्र के उपयोग सहित शुल्क

संग्रह प्रणालियों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जहां स्कूलों में शुल्क भुगतान के लिए यूपीआई या अन्य डिजिटल तरीकों के उपयोग पर अभी तक कोई राष्ट्रीय अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं किया गया है, वहीं शिक्षा मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2025 के अपने अ.शा. पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे जहां भी संभव हो, सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में प्रवेश और परीक्षा शुल्क संग्रह के लिए डिजिटल प्रणालियों का पता लगाएं, उनका सहयोग करें और उन्हें क्रियान्वित करें। यह सलाह अभिभावकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान तंत्र को प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

*****